दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 07 अप्रैल 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 186

महत्वपूर्ण एवं खास

आरोग्य निधि योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों के लिए 20 लाख का प्रावधान

नईदिल्ली (आरएनएस)। दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित रोगों के रोगियों को सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज मिलेगा। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि हाल ही में अधिसूचित दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 में राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है, उन दुर्लभ बीमारियों के लिए जिन्हें एक बार उपचार (दुर्लभ बीमारी नीति में समूह 1 के तहत सूचीबद्ध रोग) की आवश्यकता होती है। इस वित्तीय सहायता के लिए लाभार्थी को बीपीएल परिवार से होना जरूरी नहीं है। यानी बीपीएल के बाहर का व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकता है लेकिन यह लाभ लगभग 40 प्रतिशत आबादी को दिया जाएगा, जो आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत पात्र हैं। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए यह वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) योजना के तहत प्रस्तावित है, न कि आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत। इसके अलावा, रेयर डिजीज पॉलिसी में एक क्राउडफंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना की गई है जिसमें कॉरपोरेट्स और आम लोगों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए एक मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एकत्रित की गई धनराशि का उपयोग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस द्वार सभी तीन श्रेणियों की दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए किया जाएगा और शेष वित्तीय संसाधनों का उपयोग अनुसंधान के लिए भी किया जा सकता है।

तरुण बजाज बने राजस्व विभाग के सचिव

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्रालय में मंगलवार को सचिव स्तर पर फेरबदल हुई। इसके तहत आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव का जिम्मा संभाल रहे तरुण बजाज को राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दी गई है।

45 साल से ऊपर के सभी सरकारी कर्मचारी लगवाएं कोरोना वैक्सीन

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्र सरकार ने 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के अपने सभी कर्मचारियों को टीका लगवाने को कहा है ताकि कारगर रूप से कोविड-19 के प्रसार को काबू में किया जा सके। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों से कहा गया है कि वे टीकाकरण के बाद भी बार-बार हाथ धोएं, मास्क पहनें और सामाजिक दूरी का पालन करके कोविड उचित व्यवहार का पालन करें। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और कोविड-19 के प्रसार को रोकने में टीकाकरण के लिए समूहों की प्राथमिकता की नीति के आधार पर अभी 45 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय समय-समय पर एहतियाती निर्देश जारी करता रहा है ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके।

केन्द्र ने नक्सलियों के खात्मे के लिए बनाई ठोस योजना

» छत्तीसगढ़ नक्सली हमले को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में दो हफ्ते से भी कम समय में दूसरा नक्सली हमला हो गया। इन घटनाओं में सुरक्षा बलों के 27 जवान शहीद हो गए जबकि कुल 46 जवान घायल हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत का ध्यान खींचने वाले बीजापुर हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने घटना में घायल जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और हौसला आफजाई की। शाह ने जवानों के साथ खाना भी खाया। उससे पहले शाह ने दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक की जिसमें देश को स्तब्ध कर देने वाले ताजा नक्सली हमले के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई।

नक्सलियों के खिलाफ होगी निर्णायक कार्रवाई

उसके बाद छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ भी चर्चा की। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने भी केंद्र सरकार को भरपूर साथ देने का आश्वसान दिया। कहा

जा रहा है कि महीने भर में ही केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू हो सकती है। सूत्रों की मानें तो सुरक्षा बल ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए हैं। उन्हें बिल्कुल पिन-पॉइंटेड ऑपरेशन करने का खाका खींचने के कहा गया है ताकि गुरिल्ला दल में शामिल नक्सलियों का पूरी तरह सफाया किया जा सके। गृह मंत्री शाह ने कहा भी कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और सुरक्षा बलों के शौर्य एवं शहादत की तार्किक परिणति सामने आएगी। उन्होंने कहा कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई को तेज किया जाएगा और आखिर में हमारी ही जीत होगी। राज्य सरकार के कई सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि नक्सली कमांडर हिडमा को मार गिराने की योजना बन गई है। वो केंद्र और राज्य सरकारों के निशाने पर आ गया है। हिडमा ही पिछला हमला करवाया था और उसी की अगुवाई में पिछले एक दशक में कई बड़े नक्सल हमले हुए हैं।

शाह और सीएम के साथ बड़े अफसरों की मीटिंग

सुरक्षा बलों पर ताकुलगुड़ा में हुए बर्बर हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय गृह सचिव एके भल्ला, भारत सरकार के सुरक्षा सलाहकार के विजयकुमार, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह, आईबी के डायरेक्टर अवरिंद कुमार, छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी, स्पेशल डीजी (नक्सल ऑपरेशन) अशोक जुनेजा और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की सोमवार को मीटिंग हुई। एक अधिकारी ने बताया, इस रिव्यू मीटिंग में माओवादियों के खिलाफ अभियानों की विस्तृत योजना का खाका तैयार किया गया है। माओवादियों के खिलाफ लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और सुरक्षा बलों के शौर्य एवं शहादत की तार्किक परिणति सामने आएगी। उन्होंने कहा कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई को तेज किया जाएगा और आखिर में हमारी ही जीत होगी।

सुकमा के जंगलों से होगा नक्सलियों का सफाया

इसके अलावा, तेलंगाना और ओडिशा की सीमा से सटे सुकमा के जंगलों में सक्रिय कुछ और माओवदी कमांडरों की सूचना भी जुटाई जा चुकी है। सूत्रों ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ जल्द ही संयुक्त अभियानों की शुरुआत हो सकती है। दरअसल, बस्तर डिविजन का दक्षिणी इलाके में माओवादियों का गढ़ है। माओवादी यहां अपनी गतिविधियों को अंजाम देकर जंगल के अंदर ही अंदर महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा की तरफ भाग निकलते हैं। यहां बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए माओवादियों के गुरिल्ला दस्ता दूसरे क्षेत्रों से भी आते हैं।

अब प्राइवेट कंपनियों की मिसाइल देंगी दुश्मन को मात

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मिसाइल सिस्टम को विकसित करने और उत्पादन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की फर्मों को अनुमति दे दी है। ये फैसला घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।

डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने आरएनएस को बताया, डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर (डीसीपीपी) प्रोग्राम के तहत हमने प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ मिसाइल सिस्टम विकसित करने और फिर उनका उत्पादन करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भागीदारी के लिए बहुत उत्साह दिखाया है। वर्टिकली लॉन्च की शॉर्ट-रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (वीएल-एसआरएसएएम) परियोजना के लिए बोलियां भी लगी हैं।यह प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार की मेक इन इंडिया परियोजना के तहत किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में डीआरडीओ ने देश को रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी। डीआरडीओ ने इसी माह एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) टेक्नोलॉजी का आखिरी टेस्ट पूरा कर लिया है। भारतीय पनडुब्बियों को और भी ज्यादा घातक बनाने की दिशा में इसे बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया के कुछ विकसित देशों के पास ही अभी यह टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से पनडुब्बियों में ना तो ज्यादा तेज आवाज होगी और ना ही दुश्मन उसका जल्दी भनक ही लगा पाएगा।

सुपरकम्प्यूटिंग में अग्रणी मार्गदर्शक के रूप में उभर रहा है भारत

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन (एएसएम) के साथ उच्च शक्ति कंप्यूटिंग में एक अग्रणी मार्ग दर्शक के रूप में तेजी से उभर रहा है, जो इसेशिक्षा या शोध के क्षेत्र, शोधकर्ताओं, एमएसएमईकी बढ़ती कम्प्यूटेशनल मांगों को पूरा करने और तेल की खोज, बाढ़ की भविष्यवाणी और जीनोमिक्स और मादक पदार्थों की बरामदगी जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअपके लिए प्रोत्साहित रहा है।

कम्प्यूटिंग बुनियादी ढांचे को पहले से ही चार प्रमुख संस्थानों में

स्थापित किया जा चुका है और 9 और संस्थानों में तेजी से स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। सितंबर 2021 में एनएसएमके दूसरे चरण केपूरा होने के साथ ही देश की कंप्यूटिंग शक्ति 16 पेटाफ्लॉप्स (पीएफ) हो जाएगी। भारत में जमाव और विनिर्माण के साथ सुपरकंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए भारत के कुल 14 प्रमुख संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें आईआईटी, एनआईटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और आईआईएसईआरशामिल हैं।

एएसएम के पहले चरण में नियोजित बुनियादी ढांचे को पहले ही स्थापित किया जा चुका है और जल्द ही इसका दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस वर्ष शुरू किया गया चरण 3, कंप्यूटिंग गति को लगभग 45 पेटाफ्लॉप तक ले जाएगा। इसमें राष्ट्रीय सुविधा के रूप में प्रत्येक 3 पीएफ की तीन प्रणालियां और 20पीएफकी एक प्रणाली शामिल होगी।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन को देश में अनुसंधान क्षमताओं और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था ताकि उन्हें सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के लिए रीढ़के रूप में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) के साथ जोड़ा जा सके। एनएसएम पूरे देश में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सुपरकंप्यूटिंग सुविधाओं का एक ग्रिड स्थापित कर रहा है।

न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकट रमण होंगे देश के अगले प्रधान न्यायाधीश

» राष्ट्रपति ने दी नियुक्ति को मंजूरी, 24 अप्रैल को लेंगे शपथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकट रमण को मंगलवार को देश नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े के स्थान पर की गयी है जो 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, न्यायमूर्ति रमण 24 अप्रैल को भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर प्रभार संभालेंगे। न्यायमूर्ति रमण 26 अगस्त, 2022 तक देश के प्रधान न्यायाधीश रहेंगे। अधिसूचना के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकट रमण को 24 अप्रैल 2021 से भारत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। सूत्रों ने बताया कि परंपरा के मुताबिक, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा और कानून मंत्रालय में सचिव (न्याय) बरुण मित्रा ने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किया हुआ नियुक्ति पत्र आज सुबह न्यायमूर्ति रमण को सौंपा। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बोबडे ने उनके बाद पद संभालने के लिए न्यायमूर्ति रमण के नाम की परंपरा और वरिष्ठता क्रम के अनुरूप हाल ही में अनुशंसा की थी। सीजेआई की ओर से केंद्र सरकार को अनुशंसा उस दिन की गई थी जब उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति रमण के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी की शिकायत पर उचित तरीके से विचार करने के बाद खारिज करने के फैसले को सार्वजनिक किया था। नियम के मुताबिक मौजूदा प्रधान न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले एक लिखित पत्र भेजा जाता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में 27 अगस्त, 1957 को जन्मे, न्यायमूर्ति रमण 10 फरवरी, 1983 में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए गए थे। उन्हें 27 जून, 2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया और वहह 10 मार्च, 2013 से 20 मई,2013 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत रहे। उन्हें दो सितंबर, 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया और 17 फरवरी, 2014 को उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति रमण ने शीर्ष अदालत में कई हाई-प्रोफाइल मामलों को सुना है। न्यायमूर्ति रमण की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की वृहद पीठ को भेजने से पिछले साल मार्च में इनकार कर दिया था।

भाजपा के लिए दल से बड़ा देश: मोदी

» पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले पीएम

नई दिल्ली (आरएनएस)। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा मुख्यालय दिल्ली में आयोजित बड़े कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं की सेवा कैसे की जाती है। कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। भाजपा ने हमेशा पार्टी व्यक्ति से बड़ी होती है और राष्ट्र पार्टी से बड़ा होता है के मंत्र पर काम किया है। यह परंपरा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद से जारी है और आज तक चल रही है। मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आकार और विस्तार देने वाले हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे अनेकों वरिष्ठों का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है। देश का शायद ही कोई राज्य या जिला होगा, जहां पार्टी के लिए 2-3 पीढ़ियां न खप गई हों। डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया, ऐसे अनगिनत महान व्यक्तित्वों को भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से वह श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

देश में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर

» 24 घंटे में देश में करीब 97 हजार नए केस, 446 मौतें

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में इन दिनों कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। एक लाख से अधिक कोरोना मरीज मिलने के एक दिन बाद संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। देश में बीते 24 घंटे में 96,982 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 446 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में बीते 24 घंटों मे 96,982 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं

446 मरीज कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,26,86,049 पहुंच गए हैं और कोविड से मरने वालों की संख्या 1,65,547 हो गई। बता दें कि इससे एक दिन पहले सोमवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1,03,558 नए मामले दर्ज किए गए और 478 मरीजों की मौत हो गई। आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 27 दिनों से नए मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही उपचाराधीन मामलों की संख्या भी बढ़कर 7,88,223 हो गई, जो कुल मामलों का 6.21 प्रतिशत है। देश में 12 फरवरी को सबसे कम 1,35,926 उपचाराधीन मामले थे, जो उस समय के कुल मामलों का 1.25 प्रतिशत थे। आंकड़ों के अनुसार, देश में 1,17,32,279, लोग अभी तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। हालांकि मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर में गिरावट आई है और वह अब 92.48 प्रतिशत है। वहीं, कोविड-19 से मृत्यु दर 1.30 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण के पहले चरण में 92 प्रतिशत लक्ष्य हुआ पूरा

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके तहत योजना के पहले चरण में यानी 2016-17 से 2018-19 तक 92 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है। सरकार को भरोसा है कि स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल सभी घर अमृत महोत्सव के अंत तक पूरे हो जाएंगे।

2011 के एसईसीसीडेटाबेस का उपयोग करके पहचान की गई मौजूदा स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) के हिसाब से अब तक 2.14 करोड़ लाभार्थी पात्र पाए गए हैं। हालांकि इस सूची में शुरू में 2.95 करोड़ परिवार शामिल थे, मंजूरी के समय पर सत्यापन सहितकई स्तरों पर किए गए सत्यापन के माध्यम से, बहुत सारे घरों को पात्र नहीं पाया गया। इसलिएइस सूचीको 2.14 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। आगे यह संख्या और कम होने की संभावना है। इसे देखते हुए 1.92 करोड़ (90 प्रतिशत) मकानों को मंजूरी दी गयी है और मंजूरी पाने वाले मकानों में से 1.36 करोड़ (71 प्रतिशत) आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना के पहले चरण में यानी 2016-17 से 2018-19 तक एक करोड़ घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 92 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो गया है।

वित्त वर्ष 20-21 मेंबजटीय सहायता के रूप में कुल 19,269 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा, 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान की गई। कुल मिलाकर 39,269 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी जो योजना शुरू होने के बाद से किसी भी वर्ष में जारी की गयी सबसे ज्यादा राशि है। राज्यों की हिस्सेदारी सहित राज्यों द्वारा किए गए व्यय में मौजूदा वित्त वर्ष में 46,661 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो योजना शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा है।

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि 2014-15 से, आवास कार्यों की गति में काफी तेजी आई है, जिसमें पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना भी शामिल है। कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन के अलावा निर्माण कार्य पूरा होने और अन्य सुधारों पर जोर देने के कारण लगभग 73 लाख इंदिरा आवास योजनाघरों का निर्माण पूरा हुआ। इस तरह 2014-15 के बाद सेविभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत लगभग 2.10 करोड़आवास इकाइयों का निर्माण पूराहुआ है।

कुछ कार्यान्वयन सुधारों की शुरूआत के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीणके तहत, सरकार ने मकानों के निर्माण की गति और गुणवत्ता में सुधार करने, लाभार्थियों को समय पर धनराशि जारी करने का काम,लाभार्थियों के खाते में धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण एवं लाभार्थियों के लिए तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने और एमआईएस-आवाससॉफ्ट तथा आवासऐप के माश्यम से कड़ी निगरानी करने का लक्ष्य रखा है।